

# DAILY CURRENT AFFAIRS

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 29-05-25



## The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

### Thursday, 29 May, 2025

## Edition : International Table of Contents

<b>Page 01</b> <b>Syllabus : Prelims Fact</b>	अप्रैल में आईआईपी वृद्धि दर आठ महीने के निचले स्तर 2.7% पर आ गई
<b>Page 03</b> <b>Syllabus : GS 2 &amp; 3 : Social Justice and Environment</b>	नर्डल स्पिल एक चेतावनी है: विशेषज्ञ
<b>Page 04</b> <b>Syllabus : Prelims Fact</b>	कैबिनेट ने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी; परिव्यय ₹2.07 लाख करोड़ है
<b>Page 06</b> <b>Syllabus : GS 2 : Social Justice</b>	‘भारत में कैंसर देखभाल में अपर्याप्त निदान सेवाएं अभी भी एक गंभीर कमी हैं’
<b>Page 10</b> <b>Syllabus : GS 2 : Indian Polity</b>	उपसभापति का महत्व
<b>Page 08 : Editorial Analysis:</b> <b>Syllabus : GS 3 : Indian Economy</b>	भारत के वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में बदलाव की जरूरत है



सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने अप्रैल 2025 के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) डेटा जारी किया, जिसमें दिखाया गया कि भारत की औद्योगिक वृद्धि आठ महीने के निचले स्तर 2.7% पर आ गई, जिससे कई प्रमुख क्षेत्रों में कमजोर गति के बारे में चिंताएँ बढ़ गईं।

## आईआईपी डेटा की मुख्य विशेषताएँ:

### 1. समग्र आईआईपी वृद्धि:

- अप्रैल 2025 में औद्योगिक उत्पादन 2.7% बढ़ा, जो अगस्त 2024 (जिसमें 0% वृद्धि दर्ज की गई) के बाद सबसे धीमी गति है।

### 2. क्षेत्रवार प्रदर्शन:

- खनन और उत्खनन: 0.2% की गिरावट, अगस्त 2024 के बाद सबसे खराब।
- बिजली: 1.1% तक धीमी हुई, जो अगस्त 2024 के बाद सबसे कम है।
- प्राथमिक वस्तुएँ: 0.4% तक सिकुड़ी, जो कम आधार उत्पादन को दर्शाती है।
- विनिर्माण: 3.4% की वृद्धि के साथ मध्यम सुधार देखा, जो तीन महीने का उच्चतम स्तर है।
- पूंजीगत सामान: 20.3% की मजबूत वृद्धि, जो संभावित निवेश पुनरुद्धार का संकेत देती है।
- उपभोक्ता टिकाऊ सामान: रबी फसल, शादी के मौसम और ऑटो सेक्टर की मदद से विकास दर बढ़कर 6.4% हो गई।
- उपभोक्ता गैर-टिकाऊ सामान: 1.7% सिकुड़ा, पाँच महीनों में चौथा संकुचन।

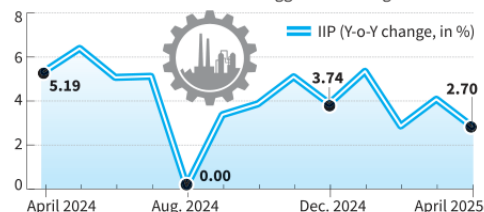
### आर्थिक व्याख्या:

- पूंजीगत सामान में तेज वृद्धि निवेश गतिविधि में पुनरुद्धार के शुरुआती संकेत देती है।
- उपभोक्ता गैर-टिकाऊ सामान में लगातार संकुचन कमजोर ग्रामीण मांग या खपत में मंदी का संकेत देता है।
- उपभोक्ता टिकाऊ सामान के प्रदर्शन को अच्छे कृषि उत्पादन और त्यौहारी/शादी की मांग जैसे मौसमी कारकों का समर्थन मिला।

## IIP growth falls to eight-month low of 2.7% in April

### In the slow lane

Lower activity in the mining, electricity, construction, and consumer non-durables sectors dragged down IIP growth



SOURCE: CMIE

**T.C.A. Sharad Raghavan**  
NEW DELHI

Growth in industrial activity in the country slowed to an eight-month low of 2.7% in April 2025, dragged down by lower activity in several sectors, including mining and quarrying, electricity, primary goods, infrastructure and construction, and consumer non-durables, according to the Index of Industrial Production (IIP) for April 2025 released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation on Wednesday.

Growth in industrial activity was last slower in August 2024, when the IIP value stayed at 0.0%, showing no growth.

In April this year, the mining and quarrying sector shrank 0.2%, its worst performance since August 2024.

#### Capital goods growth

Notably, the capital goods sector saw very strong growth of 20.3% in April 2025, albeit on a low base of 2.81% in April last year.

The manufacturing sector also saw a growth of 3.4%, a three-month high.

The electricity sector saw growth slowing to 1.1%

in April, also the slowest since August 2024.

Similarly, the primary goods category contracted by 0.4% in April, an eight-month low.

“On the forefront was a smart increase in capital goods supported by both electrical and non-electrical machinery,” Madan Sabnavis, chief economist at the Bank of Baroda said. “While there was a favourable base effect, growth of 20.3% is impressive. It needs to be seen if this is maintained in the coming months as one is looking at investment to pick up.”

#### Consumer durables

The consumer durables segment saw growth quickening to 6.4%, a three-month high.

“The successful rabi crop as well as the upcoming marriage season has helped to prop up production,” Mr. Sabnavis added. “The auto sector was also a driver of production with growth of 15.4%.”

The consumer non-durables sector, however, shrank 1.7% in April 2025, the third consecutive quarter of contractions. In fact, the sector has contracted in four out of the last five months.

- बिजली और खनन क्षेत्र में मंदी सुस्त बुनियादी ढांचे या भारी उद्योगों की मांग की ओर इशारा करती है।

### निहितार्थ:

- आईआईपी औद्योगिक गतिविधि का एक प्रमुख उच्च आवृत्ति संकेतक है।
- पूंजीगत सामान में वृद्धि को अक्सर अर्थव्यवस्था में निवेश भावना के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है।
- क्षेत्रीय विविधताएं भारतीय विनिर्माण में संरचनात्मक चुनौतियों और अवसरों को समझने में मदद करती हैं।

### UPSC Prelims Practice Question

**प्रश्न:** अप्रैल 2025 के लिए भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में हाल के रुझान को निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से समझाता है?

- a) उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं में पाँच महीनों में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई।
- b) पूंजीगत वस्तुओं में खराब निवेश भावना के कारण गिरावट दर्ज की गई।
- c) खनन और प्राथमिक वस्तुओं के क्षेत्रों में संकुचन देखा गया।
- d) बिजली उत्पादन में दोहरे अंकों की वृद्धि के साथ तेज सुधार देखा गया।

**उत्तर:** c)

लाइबेरिया के मालवाहक जहाज एमएससी ईएलएसए3 के डूबने के बाद केरल तट पर एक बड़ी पर्यावरणीय चिंता उभरी है, जिसके कारण तिरुवनंतपुरम के वर्कला और कोचुवेली जैसे स्थानों पर प्लास्टिक के छर्रे (नर्डल) बहकर तट पर आ गए। विशेषज्ञों ने इसे भारत में नर्डल रिसाव की पहली बड़ी घटना और भारत के तटीय और समुद्री पर्यावरण शासन के लिए एक चेतावनी करार दिया है।

## Nurdle spill is a wake-up call: expert

While not inherently toxic, plastic pellets remain a dangerous pollutant; their short- and long-term impacts include habitat contamination and breaking down into micro and nano plastics, and entering the food chain, says expert

**Tiki Rajwi**

THIRUVANANTHAPURAM

**T**iny plastic pellets (nurdles) found on beaches in Thiruvananthapuram following the sinking of the container vessel *MSC ELSA3* could have serious implications for the marine and coastal ecosystems and humans, warn experts.

While not inherently toxic, the pellets remain a dangerous pollutant. Their short- and long-term impacts include habitat contamination and their breaking down into micro and nano plastics and entering the food chain, according to A. Biju Kumar, Senior Professor, Marine Monitoring Lab, Depart-



Plastic pellets from the sunken Liberian ship's cargo that washed up on a coastal road in Thiruvananthapuram. NIRMAL HARINDRAN

ment of Aquatic Biology and Fisheries, University of Kerala.

The 'nurdle spill' on Kerala's coast is a wake-up call for India's coastal management, shipping safety, and marine conservation, Dr. Biju Kumar said on Wed-

nesday after conducting field verifications at the Varkala and Kochuveli beaches in Thiruvananthapuram. "While the crew of the *MSC ELSA3* were safely rescued, the ocean remains at risk," he said, describing this as the

first major incident of plastic nurdle landings in India caused by a shipwreck.

Classified as primary microplastics, these pellets and are between 1 mm and 5 mm in diameter. They constitute a major component in the global plastic chain. According to Dr. Biju Kumar, the pellets found in Kochuveli are mostly low-density polyethylene (LDPE) and high-density polyethylene (HDPE). They are the most commonly used material for manufacturing products such as plastic bags and films, flexible tubing, coatings for paper cartons and cables, detergent bottles, hard plastic containers, pipes and crates. They are also used in packaging mate-

rial, household goods, electronics and automotive parts and medical equipment. LDPE is quite difficult to recycle, he said.

### Volunteers enlisted

The State has enlisted volunteers to remove piles of plastic granules washed ashore. The police will use drones to survey the State's beaches.

The Chief Minister's Office (CMO) stated that the government has prepared rapid response teams under the command of the State Pollution Control Board to remove oil slicks and other hazardous materials that are running ashore and posing a threat to fishermen and the marine environment.

### नर्डल्स क्या हैं?

- नर्डल्स छोटे प्लास्टिक के छर्रे होते हैं, जो आमतौर पर 1-5 मिमी व्यास के होते हैं, जिनका उपयोग प्लास्टिक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इन्हें प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और ये कम घनत्व वाले पॉलीइथिलीन (LDPE) और उच्च घनत्व वाले पॉलीइथिलीन (HDPE) जैसे पॉलिमर से बने होते हैं।

## पर्यावरण और पारिस्थितिकी संबंधी चिंताएँ:

### 1. विषाक्त नहीं, लेकिन प्रदूषक:

- हालांकि स्वाभाविक रूप से विषाक्त नहीं, नर्डल्स एक प्रमुख समुद्री प्रदूषक हैं।
- वे माइक्रो और नैनो प्लास्टिक में टूट जाते हैं, आवासों को दूषित करते हैं और समुद्री खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं।

### 2. समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान:

- ये प्लास्टिक कण लगातार कार्बनिक प्रदूषकों (POPs) को अवशोषित कर सकते हैं और समय के साथ विषाक्त हो जाते हैं।
- वे समुद्री जीवों द्वारा आसानी से निगले जाते हैं, जिससे जैव संचय और संभावित मानव स्वास्थ्य जोखिम होते हैं।

### 3. मत्स्य पालन और आजीविका पर प्रभाव:

- तटीय प्रदूषण मछुआरों की आजीविका को प्रभावित करता है, मछली पालन के मैदानों को नुकसान पहुँचाता है, और पकड़ की गुणवत्ता को कम करता है।

### 4. पुनर्चक्रण करना कठिन:

- एलडीपीई को पुनर्चक्रण करना विशेष रूप से कठिन है, जो दीर्घकालिक अपशिष्ट प्रबंधन चुनौतियों को बढ़ाता है।

## प्रशासनिक और नीतिगत प्रतिक्रिया:

#### • राज्य की प्रतिक्रिया:

- समुद्र तट की सफाई के लिए स्वयंसेवकों को जुटाया गया।
- प्रभावित तटीय क्षेत्रों की निगरानी के लिए पुलिस ड्रोन तैनात किए गए।
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नेतृत्व में त्वरित प्रतिक्रिया दल तेल के छींटों और प्लास्टिक कचरे को संभाल रहे हैं।

#### • व्यापक नीतिगत प्रतिबिंब:

- यह घटना समुद्री सुरक्षा प्रोटोकॉल में खामियों, खतरनाक कार्गो विनियमन के कमजोर प्रवर्तन और समुद्री प्रदूषण आकस्मिक योजना की कमी को उजागर करती है।



## UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: केरल तट पर हाल ही में हुआ नर्डल रिसाव समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने में भारत की तैयारियों के बारे में एक चेतावनी है। ऐसे रिसावों के कारणों और प्रभावों की जांच करें और टिकाऊ तटीय और समुद्री प्रबंधन के लिए एक व्यापक नीति प्रतिक्रिया का सुझाव दें। (250 Words)

Page : 04 : GS 3 : Indian Economy : Agriculture

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2025-26 के विपणन सत्र के लिए 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है, जिसका कुल बजटीय परिव्यय ₹2.07 लाख करोड़ है। इस कदम का उद्देश्य किसानों को लाभकारी रिटर्न सुनिश्चित करना और कृषि कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करना है।

# Cabinet approves hike in MSP for kharif crops; outlay stands at ₹2.07 lakh crore

**The Hindu Bureau**  
NEW DELHI

The Cabinet Committee on Economic Affairs chaired by Prime Minister Narendra Modi on Wednesday approved the increase in the Minimum Support Price (MSP) for 14 kharif crops for 2025-26. The total outlay is nearly ₹2.07 lakh crore.

“Government has increased the MSP of kharif crops for marketing season 2025-26 to ensure remunerative prices to the growers for their produce,” a press statement from the Ministry of Agriculture stated.

The highest absolute increase in MSP over the previous year has been recommended for nigerseed (₹820 a quintal) followed by ragi (₹596), cotton (₹589) and sesamum (₹579).

In 2024-25, the MSP for nigerseed was ₹8,717 a



The expected margin over production cost is highest in the case of bajra.

quintal, which has been revised to ₹9,537 for the same quantity.

Similarly for ragi, the MSP of ₹4,290 a quintal has been revised to ₹4,886. As for cotton, the MSP of medium staple variety has been revised from ₹7,121 to ₹7,710 and for long staple variety, from ₹7,521 to ₹8,110.

For sesamum, the MSP has been revised from ₹9,267 to ₹9,846.

The increase in MSP for kharif crops is in line with the Union Budget 2018-19 announcement of fixing

the MSP at a level of at least 1.5 times the all-India weighted average cost of production, the statement said.

“The expected margin to farmers over their cost of production are estimated to be highest in case of bajra (63%) followed by maize (59%), tur (59%) and urad (53%). For the rest of the crops, the margin to farmers over their cost of production is estimated to be at 50%,” it further said.

In recent years, the government has been promoting the cultivation of nutri-cereals, or “Shree Anna”, by offering a higher MSP for these crops.

During the period 2014-15 to 2024-25, procurement of 14 kharif crops amounted to 7,871 lakh tonnes, while during the period 2004-05 to 2013-14, the procurement was 4,679 lakh tonnes, the statement said.

## एमएसपी वृद्धि की मुख्य विशेषताएं:

- एमएसपी संशोधन: सभी 14 खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की गई है, जिसमें नाइजरसीड में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है, उसके बाद रागी, कपास और तिल का स्थान है।
- लाभ मार्जिन: उत्पादन लागत पर अपेक्षित मार्जिन है:

## बाजरा (63%) के लिए सबसे अधिक

- उसके बाद मक्का और तुअर (59%), और उड़द (53%)
- शेष फसलों के लिए, मार्जिन को 50% पर रखा गया है, जो बजट 2018-19 के वादे के अनुरूप है।
- पोषक अनाज पर ध्यान: हाल के वर्षों में, पोषक अनाज या "श्री अन्न" जैसे रागी और बाजरा के लिए उच्च एमएसपी की पेशकश की गई है, जिससे पोषण और जलवायु लचीलापन मूल्य के कारण उनकी खेती को बढ़ावा मिला है।

## यह क्यों मायने रखता है:

- **यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए:**
  - एमएसपी तंत्र को समझना
  - पूर्ण एमएसपी वृद्धि और लागत पर लाभ मार्जिन के बीच अंतर
  - उच्चतम वृद्धि/लाभ मार्जिन वाली फसलों की पहचान
  - एमएसपी नीति का केंद्रीय बजट 2018-19 से संबंध

## यूपीएससी मुख्य परीक्षा (जीएस पेपर III) के लिए:

- एमएसपी कृषि मूल्य निर्धारण नीति, किसानों की आय सुरक्षा और ग्रामीण संकट प्रबंधन के लिए केंद्रीय है।
- किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है।
- जलवायु-लचीले और पोषण युक्त फसलों को बढ़ावा देने की दिशा में बदलाव पर जोर देता है।

## मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि:

### 1. किसानों को आर्थिक सुरक्षा:

- उच्च एमएसपी आय की भविष्यवाणी सुनिश्चित करता है, विशेष रूप से वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर क्षेत्रों में।



## 2. फसल विविधीकरण:

- पोषक-अनाजों के रणनीतिक मूल्य निर्धारण का उद्देश्य धान जैसी पानी-गहन फसलों से खेती को दूर करना है, विशेष रूप से अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में।

## 3. स्थिरता का पहलू:

- बाजरा और दालों को प्रोत्साहित करने से मृदा स्वास्थ्य, जल संरक्षण और पोषण सुरक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

## 4. चुनौतियाँ:

- खरीद सीमाएँ: एमएसपी तभी सार्थक है जब प्रभावी खरीद हो।
- क्षेत्रीय पूर्वाग्रह: एमएसपी खरीद अभी भी कुछ राज्यों (पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश) में प्रमुख रूप से होती है।
- मुद्रास्फीति जोखिम: एमएसपी में अत्यधिक वृद्धि से मुद्रास्फीति दबाव हो सकता है और राजकोषीय बोझ प्रभावित हो सकता है।

### UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तंत्र का उद्देश्य किसानों की आय को सुरक्षित करना, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना और ग्रामीण संकट को कम करना है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में MSP की प्रभावशीलता की आलोचनात्मक जांच करें और MSP को अधिक समावेशी और प्रभावशाली बनाने के लिए सुधार सुझाएँ। (250 Words)

नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज (एनएएमएस) की एक हालिया रिपोर्ट ने भारत में कैंसर की देखभाल में एक गंभीर कमी को उजागर किया है - पर्याप्त निदान सेवाओं की कमी, विशेष रूप से स्तन कैंसर के मामले में, जो भारतीय महिलाओं में सबसे आम घातक बीमारी है। रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि यह कमी किस तरह से देरी से निदान, देर से चरण में पता लगाने और खराब जीवित रहने की दर में योगदान देती है, जिससे कैंसर का बोझ काफी बढ़ जाता है।

# 'Inadequate diagnostic services still a critical gap in cancer care in India'

**Bindu Shajan Perappadan**

NEW DELHI

One of the critical gaps in cancer care in India is the lack of adequate diagnostic services, says the latest report by the National Academy of Medical Sciences (NAMS), an advisory body to the Union government for health policy and planning.

India records nearly 2,00,000 new cancer cases each year, the report adds.

The NAMS Task Force Report on Breast Cancer in India, published recently, notes that the proportion of patients diagnosed with breast cancer at a younger age is notably higher in India than in high income countries. Additionally, patients in India tend to present with later-stage disease compared with the western pattern. More than 60% of the patients in



Cancer cases are projected to reach 2.08 million by 2040 in India, a 57.5% increase from the 2020 figure. SPECIAL ARRANGEMENT

India present at Stages 3 or 4, while around 60% of the patients in the U.S. are diagnosed *in situ* or at Stage 1. It adds that more than 50% of the patients in India experience a delay of over three months before seeking medical care.

In India, breast cancer is the most common malignancy among women, and a leading cause of cancer-related deaths. The NAMS

established a task force to prepare a report addressing this critical issue, and said there was an urgent need for a comprehensive approach to manage the disease effectively.

"Breast cancer is treatable when diagnosed in its early stages. In India, the survival rate for patients with breast cancer is lower than in western countries due to several factors, in-

cluding the late-stage presentation, delayed initiation of definitive management, and inadequate or fragmented treatment," the paper says. The NAMS's task force is looking into developing guidelines in combating breast cancer across the Indian population.

"Sixty percent of the global population resides in Asia, which accounts for 50% of cancer cases and 58% of cancer-related deaths. India ranks third in accounting for cancer cases, following China and the United States of America. The projected cancer burden in India is estimated to reach 2.08 million by 2040, representing a 57.5% increase from 2020," the paper says. Gaps in diagnostic services, treatment modalities, and lack of awareness are among the shortcomings in cancer care in India, it adds.

## रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- विलंबित निदान: भारत में स्तन कैंसर के 60% से अधिक रोगियों का निदान चरण 3 या 4 में किया जाता है, जबकि अमेरिका में लगभग 60% चरण 1 या इन-सीटू निदान होता है।
- उपचार प्राप्त करने में अत्यधिक विलंब: 50% से अधिक रोगियों को डॉक्टर से परामर्श करने में तीन महीने से अधिक की देरी का अनुभव होता है।
- बढ़ता बोझ: भारत में कैंसर का बोझ 2040 तक 57.5% बढ़ने का अनुमान है, जो 2020 के स्तर से बढ़कर 2.08 मिलियन मामलों तक पहुँच जाएगा।

### • तुलनात्मक वैश्विक डेटा:

- एशिया में वैश्विक जनसंख्या का 60% और कैंसर के 50% मामले हैं।
- चीन और अमेरिका के बाद भारत वैश्विक स्तर पर कैंसर के मामलों में तीसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।

### • अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा:

- नैदानिक सेवाओं, उपचार तक पहुँच और सार्वजनिक जागरूकता में अंतर बना हुआ है।
- कैंसर की देखभाल खंडित और असमान रूप से वितरित है, खासकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में।

## यह क्यों मायने रखता है

### • प्रारंभिक विश्लेषण:

- NAMS की रिपोर्ट और इसकी सलाहकार भूमिका।
- डेटा बिंदु: कैंसर में भारत की वैश्विक रैंकिंग, 2040 तक अनुमानित कैंसर का बोझ, निदान में देरी।
- भारत में महिलाओं में स्तन कैंसर सबसे बड़ी बीमारी है।

## मुख्य विश्लेषण:

- स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे में मुद्दे: सस्ती और समय पर निदान तक पहुँच।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियाँ: कैंसर जैसे एनसीडी (गैर-संचारी रोग) के लिए दीर्घकालिक नीतिगत ध्यान की आवश्यकता होती है।
- लिंग और स्वास्थ्य: स्तन कैंसर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में लिंग-विशिष्ट कमजोरियों को उजागर करता है।
- स्वास्थ्य नीति और शासन: राष्ट्रीय स्वास्थ्य रणनीति को आकार देने में NAMS जैसे सलाहकार निकायों की भूमिका।



## पहचानी गई महत्वपूर्ण चुनौतियाँ:

### 1. अपर्याप्त निदान क्षमता:

- प्रशिक्षित रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजी लैब और स्क्रीनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी।
- सुविधाओं का ग्रामीण-शहरी वितरण खराब।

### 2. कम जागरूकता और सांस्कृतिक कलंक:

- जागरूकता की कमी, सामाजिक कलंक और कैंसर के डर के कारण उपचार लेने में देरी।

### 3. खंडित उपचार पारिस्थितिकी तंत्र:

- सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में एकीकृत कैंसर देखभाल मार्गों की कमी।

### 4. संसाधन और बुनियादी ढाँचे की कमी:

- गैर-संचारी रोग की रोकथाम और स्क्रीनिंग कार्यक्रमों के लिए धन का अपर्याप्त आवंटन।

## आगे बढ़ने की सिफारिशें:

- प्रारंभिक जांच और निदान के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना।
- कलंक को कम करने और स्वास्थ्य चाहने वाले व्यवहार में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान।
- आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में कैंसर देखभाल सेवाओं का एकीकरण।
- जिला और उप-जिला स्तर पर ऑन्कोलॉजी सेवाओं के लिए क्षमता निर्माण।
- शीघ्र पहचान के लिए अनुसंधान एवं डेटा प्रणालियों में निवेश करें, विशेष रूप से कमजोर समूहों के लिए।

## UPSC Mains Practice Question

**प्रश्न:** भारत में स्तन कैंसर का विलम्बित निदान और उपचार सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना में प्रणालीगत कमियों को दर्शाता है। इस संदर्भ में, भारत में कैंसर देखभाल वितरण में प्रमुख चुनौतियों का मूल्यांकन करें और उन्हें प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए नीतिगत उपाय सुझाएँ। (250 words)

लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद छह साल से अधिक समय से (2019 से) खाली पड़ा है, जिससे संवैधानिक अनुपालन, लोकतांत्रिक परंपराओं और भारत की संसदीय प्रणाली में शक्ति संतुलन के बारे में गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस पद को भरने से लगातार इनकार - विशेष रूप से विपक्ष के किसी सदस्य के साथ - को संवैधानिक और लोकतांत्रिक चिंता के रूप में देखा जा रहा है।

## The importance of the Deputy Speaker

The Deputy Speaker is not a mere substitute of the Speaker; he plays an indispensable role in maintaining the continuity of legislative work. Conventionally, this position has been handed over to the Opposition, in order to develop harmony between the ruling party and the Opposition

### LETTER & SPIRIT

C. B. P. Srivastava

**T**he position of the Deputy Speaker has been lying vacant for the last six years raising questions on constitutional adherence and democratic resilience. The position goes beyond ceremonial significance and is indispensable to parliamentary democracy. The present scenario of the vacant position could be understood through some very important questions. The framers of the Constitution adopted a parliamentary form of governance to ensure effective representation of the people of India in the political system. This idea would lose its significance if the system does not function properly, effectively and smoothly. It is also extremely important that debates and discussions between the ruling establishment and the Opposition remain proper to make the government accountable, and that checks and balances are ensured. It has been alleged that the current ruling government has vehemently denied to hand over the position of the Deputy Speaker to an Opposition member. This is against the principle of sharing of powers which is one of the mandates of a successful parliamentary democracy. It may also be noted that constitutional conventions do have statutory effect in cases of absence.

### A Deputy Speaker's role

The Deputy Speaker is not a mere substitute of the Speaker; he plays an indispensable role in maintaining the continuity of legislative work. He also presides over committees such as the private member's bill and the House Budget Committee of Parliament; oversees crucial debates; and serves as a neutral arbiter during sensitive discussions. Provisions for a Deputy Speaker is listed under Article 93 of the Constitution. The language of the Article which includes the phrase 'as soon as' for



**Vacant seat:** A view of the Lok Sabha during the Winter session of Parliament, in New Delhi, on December 16, 2024. PTI

electing both the Speaker and the Deputy Speaker implies urgency and necessity, and not discretion. Article 94 reinforces the continuity of the Deputy Speaker's office until resignation, removal, or disqualification.

Conventionally the position of the Speaker goes to the ruling party. There has been an informal practice of offering the Deputy Speaker's post to a member of the Opposition. The essence of this practice is to develop harmony between

the ruling party and the Opposition for the smooth functioning of Parliament.

### Prolonged vacancy

The Government of India did not appoint a Deputy Speaker in the 17th Lok Sabha (2019-24), and it appears now that it does not have the intention to appoint one in the 18th Lok Sabha as well. It is really unfortunate that the government and the Opposition could not come to terms on the issue of appointing a Deputy Speaker,

which could be primarily because the government does not want to give this position to the Opposition. According to Rule 8 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha 1952, election to the post of the Deputy Speaker "shall be held on such date as the Speaker may fix". The Deputy Speaker is elected once a motion proposing his or her name is moved. He enjoys the same powers as the Speaker when he presides over a sitting House. According to Article 180 of the Constitution, the Deputy Speaker has the power to conduct the duties of the Speaker when his chair is vacant. Thus, this vacancy violates not only Articles 93, 94 and 180 of the Constitution, it is also inconsistent with the Rules of Procedure.

### Constitutional implications

While Article 93 provides for the election of the Deputy Speaker "as soon as may be", it does not set a timeline. The misinterpretation of this phrase may lead to a long delay which could distort constitutional intent and create a constitutional vacuum. Conventionally, the position is handed over to the Opposition, but now that the position is vacant, authority is centralised in the Speaker and thereby in the ruling party which will be inconsistent with the democratic intent of the Constitution. In fact, constitutional conventions intend to strike a delicate balance between the ruling party and the Opposition to ensure that democratic resilience is maintained and sustained in the parliamentary system, based on the Westminster model, which mandates effective discussions and deliberations. Moreover, in a situation caused due to the resignation of the Speaker or even in case of incapacitation, a severe constitutional crisis may surface which will be detrimental to the system of governance.

Above all, the failure to uphold the tradition of offering the office to the Opposition undermines the spirit of consensus-driven politics.

C. B. P. Srivastava is President, Centre for Applied Research in Governance, Delhi

### THE GIST

Provisions for a Deputy Speaker is listed under Article 93 of the Constitution. The language of the Article which includes the phrase 'as soon as' for electing both the Speaker and the Deputy Speaker implies urgency and necessity.

While Article 93 provides for the election of the Deputy Speaker "as soon as may be", it does not set a timeline.

The Government of India did not appoint a Deputy Speaker in the 17th Lok Sabha (2019-24), and it appears now that it does not have the intention to appoint one in the 18th Lok Sabha as well.

## भूमिका और संवैधानिक प्रावधान:

- संविधान के अनुच्छेद 93 में यह अनिवार्य किया गया है कि लोक सभा (लोकसभा) दो सदस्यों - अध्यक्ष और उपाध्यक्ष - को "जितनी जल्दी हो सके" चुनेगी।
- अनुच्छेद 94 कार्यालय की निरंतरता को पुष्ट करता है, जिसमें कहा गया है कि उपाध्यक्ष तब तक पद खाली नहीं करेगा जब तक कि वह इस्तीफा न दे, अयोग्य घोषित न कर दिया जाए या हटा न दिया जाए।
- अनुच्छेद 180 उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के अनुपस्थित होने या पद रिक्त होने पर अध्यक्ष के कार्य करने का अधिकार देता है।
- लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम (1952) के नियम 8 के अनुसार अध्यक्ष को उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि तय करनी होती है।

## उपाध्यक्ष क्यों महत्वपूर्ण है?

### 1. केवल एक विकल्प नहीं:

- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है।
- सत्रों की अध्यक्षता करते समय अध्यक्ष के समान शक्तियाँ रखता है।
- सदन की बजट समिति और निजी सदस्यों के विधेयक समिति जैसी महत्वपूर्ण संसदीय समितियों की अध्यक्षता करता है।

### 2. तटस्थ मध्यस्थ:

- विशेष रूप से संवेदनशील बहसों के दौरान गैर-पक्षपातपूर्ण भूमिका निभाता है।
- सत्तारूढ़ और विपक्षी बेंचों के बीच संतुलन तंत्र के रूप में कार्य करता है।

### 3. लोकतांत्रिक परंपराओं को कायम रखना:

- पारंपरिक रूप से विपक्ष को पेश किया जाता है, जिससे द्विदलीय सहयोग को बढ़ावा मिलता है।
- अनुपस्थिति सर्वसम्मति-निर्माण और समावेशिता के वेस्टमिंस्टर-आधारित सम्मेलनों को कमजोर करती है।

## लंबे समय तक रिक्त रहने से होने वाली समस्याएँ:

- संवैधानिक भावना का उल्लंघन: जबकि संविधान एक सख्त समयसीमा निर्दिष्ट नहीं करता है, "जितनी जल्दी हो सके" वाक्यांश का अर्थ है तात्कालिकता, न कि अनिश्चितकालीन देरी।
- शक्ति का केंद्रीकरण: उपसभापति की अनुपस्थिति से अध्यक्ष में प्रक्रियात्मक शक्ति का अत्यधिक संकेंद्रण होता है, जो अक्सर सत्तारूढ़ पार्टी से संबद्ध होता है।
- संसदीय जाँच और संतुलन का क्षरण: एक रिक्त पद जवाबदेही और विधायी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए संस्थागत तंत्र को कमजोर करता है।
- संवैधानिक संकट का खतरा: यदि अध्यक्ष इस्तीफा दे देते हैं या अक्षम हो जाते हैं, तो कोई विकल्प नहीं बचता, जिससे कार्यवाही की निरंतरता को खतरा हो सकता है।

### UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: लोकसभा में उपसभापति का पद लंबे समय से खाली रहना न केवल संवैधानिक भावना का उल्लंघन करता है, बल्कि संसदीय लोकतंत्र को भी कमजोर करता है। संवैधानिक प्रावधानों, लोकतांत्रिक परंपराओं और भारत के विधायी कामकाज में इस तरह के शून्य के निहितार्थों की आलोचनात्मक जांच करें। (250 words)



## Page : 08 Editorial Analysis

# India's financial sector reforms need a shake-up

India's financial sector stands at an inflection point. For years, the government and regulators have attempted incremental reform in banking, financial services, and insurance (BFSI), yet systemic frictions persist. These frictions are not just inefficiencies. They are barriers that deter savers, discourage investors and delay growth. A truly professional, transparent and investor-friendly financial sector demands deeper structural corrections, particularly in corporate bond markets, retirement planning instruments, nomination processes across BFSI, and the growing menace of shadow banking.



**Vaishu Rai**

is a Legislative Assistants to Members of Parliament (LAMP) Fellow 2025 - PRS Legislative

### On nomination and nominees

Let us begin with the nomination conundrum. Across BFSI verticals (banks, mutual funds, insurance), the rules governing nominees are startlingly inconsistent. A citizen can nominate a single person for one account but multiple for another, with different rights attached. This patchwork approach does not have logical or legal clarity. Rather, it confuses ordinary savers and benefits only those who seek to exploit legal ambiguities, often through protracted litigation.

What public interest is served by maintaining three separate nomination regimes? A harmonised nomination framework, with clarity on nominee rights versus legal heir claims, is overdue. If the disconnect exists for a good reason, the government must share the evidence and case studies that justify it.

Zooming out, the larger structural lacuna in India's financial landscape is the underdeveloped corporate bond market. Despite years of policy pronouncements, it remains shallow, illiquid and opaque. This matters because the cost of capital is the single biggest determinant of business viability. An efficient bond market can reduce funding costs by 2% to 3%, potentially unlocking massive gains for industry and employment. The Reserve Bank of India once mandated the National Stock Exchange (NSE) to develop a secondary bond market, but this directive was quietly ignored. Why? Equity trading offers more profit, especially through opaque algorithmic

There must be a harmonisation of rules across verticals, the nurturing of a deep bond market, vibrant retirement finance and a reining in of shadow banking

strategies that have previously attracted regulatory scrutiny and journalistic exposés. When a journalist called out malpractices, the NSE responded with a ₹100-crore defamation suit, only to be admonished by the High Court later. India's bond market reform cannot be divorced from broader regulatory concerns either, particularly around transparency in capital flows. As a member of the Financial Action Task Force (FATF), India is committed to implementing global Know Your Customer (KYC) norms, which include clear identification of Ultimate Beneficial Owners (UBOs). FATF's updated guidelines in 2022 underscore the need for countries to maintain accurate and accessible ownership data to prevent misuse of financial structures.

Yet, practical implementation remains a challenge. For instance, in recent months, the Securities and Exchange Board of India (SEBI) has had to press two Mauritius-based foreign portfolio investors (Elara India Opportunities Fund and Vespera Fund) to disclose granular shareholder data related to their holdings in listed Indian firms. These funds reportedly did not comply with multiple disclosure requests, complicating regulatory oversight and delaying enforcement actions.

Moreover, India's current UBO disclosure thresholds (10% for companies and 15% for partnerships) create loopholes that allow entities to structure investments just below these limits, thereby avoiding identification. This makes it difficult for regulators to ascertain the true economic interest behind trades in Indian exchanges or bond markets, particularly when routed through jurisdictions such as Mauritius.

While this is not unique to India, opacity in ownership structures does weaken market integrity and may inhibit sustained long-term investments, both domestic and foreign.

### Retirement planning

Additionally, the long-term needs of India's young professionals, especially those in BFSI itself, remain unmet. Retirement planning in India is mostly routed through annuities – products that

are costly due to the intermediation margin taken by insurance companies.

There is a simpler and cheaper alternative that exists: long-dated zero-coupon government securities. The math is compelling, removing the 2% intermediation fee over a 30-year period leads to massive gains for the saver. We already have the technology to "strip" principal and coupon payments and offer these as zero-coupon bonds, but the government and the Reserve Bank of India (RBI) have shown little initiative. We are missing an opportunity to build a vibrant, low-cost retirement ecosystem anchored on sovereign credibility.

### Shadow banking

Then comes the most ominous blind spot: shadow banking. Non-banking financial companies (NBFCs), margin lenders, repo traders, and brokers are offering bank-like services without being subject to full regulatory oversight. This is not a fringe issue. Global economists warn that the next financial crisis could originate here, just as the 2008 financial crisis did in the United States via unregulated derivatives.

In India, retail investors are being financed by brokers who offer loans masked as margin funding. The effective interest rates in such transactions can easily exceed 20%, often without the investor even realising it. The broker holds the investor's contribution as collateral, lends it back to them, and charges interest on the full amount – a classic shadow banking trick. Does the Finance Ministry or RBI even know the scale of this lending?

The European Union has already passed legislation to gather comprehensive data on shadow banking activities. India must follow suit. Transparency must precede regulation, and data is the first step toward transparency.

India's financial sector reforms must go beyond slogans and cosmetic amendments. We need a coherent, forward-looking strategy that harmonises rules across verticals, nurtures a deep bond market, innovates in retirement finance, and reins in shadow banking.

## Paper 03 : भारतीय अर्थव्यवस्था

**UPSC Mains Practice Question :** भारत के वित्तीय क्षेत्र में सुधार टुकड़ों में और प्रतिक्रियात्मक रहे हैं। बॉन्ड मार्केट, शैडो बैंकिंग और निवेशक पारदर्शिता में उभरती चुनौतियों के मद्देनजर, भारत के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को कुशल, न्यायसंगत और भविष्य के लिए तैयार बनाने के लिए आवश्यक कदमों का गंभीरता से मूल्यांकन करें। (250 words)

- भारत का वित्तीय क्षेत्र, जिसमें बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा (BFSI) शामिल हैं, ऐसी प्रणालीगत अक्षमताओं का सामना कर रहा है जो मामूली सुधारों से कहीं आगे जाती हैं। हाल ही में LAMP फ़ेलो द्वारा दी गई राय में तर्क दिया गया है कि इस क्षेत्र को बॉन्ड बाज़ारों, नामांकन नियमों, सेवानिवृत्ति योजना और शैडो बैंकिंग में खामियों को दूर करने के लिए एक साहसिक, संरचनात्मक रीसेट की आवश्यकता है - ये सभी पारदर्शिता, निवेशक विश्वास और नियामक क्षमता से जुड़े हुए हैं।

## लेख में हाइलाइट किए गए मुख्य मुद्दे:

### 1. असंगत नामांकन नियम:

- बैंकों, म्यूचुअल फंड और बीमा उत्पादों में नामांकन के नियम अलग-अलग होते हैं।
- यह असंगतता खुदरा बचतकर्ताओं के लिए भ्रम पैदा करती है और कानूनी विवादों को जन्म देती है।
- सुसंगत कानूनी ढांचे की कमी के कारण खाताधारक की मृत्यु के बाद मुकदमेबाजी और संपत्ति लॉक-इन होती है।
- एक समान नामांकन कानून और नामांकित बनाम कानूनी उत्तराधिकारी अधिकारों के बीच स्पष्टता की आवश्यकता है।

### 2. अविकसित कॉर्पोरेट बॉन्ड बाज़ार:

- वर्षों से नीतिगत फ़ोकस के बावजूद भारत का कॉर्पोरेट बॉन्ड बाज़ार तरलताहीन और अपारदर्शी बना हुआ है।
- एक गहरा बॉन्ड बाज़ार पूंजी की लागत को काफ़ी हद तक कम कर सकता है और बुनियादी ढांचे और उद्योग के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण को सक्षम कर सकता है।
- विनियामक उपेक्षा, इक्विटी ट्रेडिंग को प्राथमिकता, और एक्सचेंजों (जैसे NSE) द्वारा लाभ-केंद्रित व्यवहार विकास को बाधित करता है।
- RBI द्वारा NSE को बॉन्ड प्लेटफ़ॉर्म विकसित करने के आदेश का पालन नहीं किया गया है।

### 3. अंतिम लाभकारी स्वामित्व (UBO) प्रकटीकरण अंतराल:

- भारत की वर्तमान UBसीमा (10%-15%) निधियों को अपारदर्शी बने रहने देती है।
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) द्वारा गैर-अनुपालन, विशेष रूप से मॉरीशस के माध्यम से, विनियामक निरीक्षण को चुनौती देता है।
- विस्तृत प्रकटीकरण का अभाव SEBI के प्रवर्तन को कमज़ोर करता है, और FATF पारदर्शिता प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करता है।

### 4. अकुशल सेवानिवृत्ति नियोजन उत्पाद:

- अधिकांश सेवानिवृत्ति बचत वार्षिकी के माध्यम से की जाती है, जो महंगी होती है और इसमें खराब रिटर्न होता है।
- शून्य-कूपन सरकारी बॉन्ड एक बेहतर विकल्प प्रदान करते हैं - लागत प्रभावी और संप्रभु-समर्थित।
- हालांकि, न तो RBI और न ही सरकार ने खुदरा निवेशकों के लिए ऐसी लंबी अवधि की प्रतिभूतियों की पेशकश करने के लिए कदम उठाए हैं।

### 5. छाया बैंकिंग जोखिम:

- NBFC, ब्रोकर और मार्जिन ऋणदाता बैंकों की तरह काम करते हैं, लेकिन पूर्ण विनियामक ढांचे के बाहर काम करते हैं।
- ब्रोकर खुदरा निवेशकों को 20% से अधिक की छिपी हुई ब्याज दरों के साथ मार्जिन ट्रेडिंग के तहत उधार देते हैं, जिससे खुदरा ऋण जाल का जोखिम होता है।
- भारत में ऐसी गतिविधियों के व्यापक डेटा और विनियामक कवरेज का अभाव है - जिससे वित्तीय संकट का जोखिम बढ़ जाता है।

### विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि:

- वित्तीय समावेशन को विनियामक स्पष्टता और निवेशक सुरक्षा के साथ-साथ चलना चाहिए।
- भारत का सुधार आख्यान वृद्धिशील रहा है, लेकिन अब वित्तीय वास्तुकला में मूलभूत सुधारों की मांग करता है।
- कानूनों का विखंडन, विनियामक मध्यस्थता और अपारदर्शी वित्तीय प्रवाह निवेशकों का विश्वास कम करते हैं और असमानता को बढ़ाते हैं।
- सुसंगत वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और कानूनी सामंजस्य का उपयोग किया जाना चाहिए।